The question was put and the motion was adopted.

श्री एस॰ एस॰ अहलूवालिया : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

The Jharkhand Atomic Authority Bill, 2005

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, I beg for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an Atomic Authority for the purpose of setting up an atomic power plant for generating electricity in the State of Jharkhand and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order (Delhi Amendment) Bill, 2005

SHRI MOOLCHAND MEENA (Rajasthan): Sir, I beg for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI MOOLCHAND MEENA: Sir, I introduce the Bill.

The Patents (Amendment) Bill, 2005

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Patents, Act. 1970.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, I introduce the Bill.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

Appointment of Commission of Inquiry to Probe into Land Allotments made by DDA during 1999—2003—contd.

MR. CHAIRMAN: Further discussion on the Resolution moved by Shri V. Narayanasamy on the 10th December, 2004, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि डिबेट तो पूरी हो चुकी हैं । मैं समझता हूं कि जवाब हो जाए तो ...(व्यवधान)...

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार): सर, मुझे दो मिनट बोलने का मौका दिया जाए, ज्यादा नहीं।. ...(व्यवधान)... मेरा निवेदन है कि मैं केवल दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: ठीक है, बोलिए, लेकिन और कोई नहीं बोलेगा।

प्रो॰ राम देव भंडारी: माननीय सभापति जी, श्री वी॰ नारायणसामी द्वारा प्रस्तुत संकल्प, जिसमें डी॰ डी॰ ए॰ में 1999 और 2003 के बीच जो बड़े पैमाने पर भूमि का घोटाला हुआ है, मेरी जानकारी के अनुसार 2000 प्लॉट, कुछ संगठन और कतिपय संगठन, जो उस समय दिल्ली की सरकार से जुड़े हुए थे, उनको औने-पौने दामों में, बहुत सस्ते दामों में दिए गए।

यदि उसकी कीमत मार्किट रेट से लगाई जाए तो बीस हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): सभापति महोदय, इस विषय पर पिछले दिनों चर्चा हो चुकी है। ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): आप 99 से नहीं 85 से करवाइए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिए, आप दोनों बैठ जाइए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: आप उसकी मांग कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप जल्दी खत्म करिए, दो मिनट निकल गए हैं।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, यह जो संकल्प है, उसमें 1999 से लेकर ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): सर, आपने इनको बालने की अनुमति दी है, इस पर पिछले हफ्ते ढ़ाई घंटे चर्चा हो चुकी है और हर तरफ से आरोप-प्रत्यारोप हो चुके हैं। हमारी तो यह मांग है कि जब से डी॰डी॰ए॰ बना है, तब से उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। ...(व्यवधान)... इन्क्वायरी तो हो ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बस हो गया और आपने चार्ज लगा दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: अरे भाई सुनिए ...(व्यवधान)... इन्क्वायरी क्यों न हो ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: आप सीनियर मैम्बर हैं ...(व्यवधान)... 1999 से लेकर 2003 तक ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: भंडारी जी, हो गया। आपने जो चार्ज लगाया, वह लगा दिया, अब खत्म करिए। ...(**व्यवधान**)... पिछले सेशन में यह हो गया है। ...(व्यवधान)... पिछले सत्र में यही हुआ है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, एक हजार का घोटाला ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है, आपने कह दिया।

प्रो॰ राम देव भंडारी: हजार बार इसी सदन में चर्चा हो चुकी है और यह बीस हजार करोड़ का घोटाला ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है, आपने कह दिया है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: यदि इसकी चर्चा सदन में न हो ...(**व्यवधान**)...

सभापति: हो गई चर्चा, आपने दो मिनट मांगे थे और आपने दो मिनट में कह दिया।

प्रो॰ राम देव भंडारी: देश की जनता के साथ न्याय करें या दिल्ली की जनता के साथ न्याय ...(**व्यवधान**)... महोदय, डी॰डी॰ए॰ का गठन इस उद्देश्य से हुआ था कि जो दिल्ली के गरीब लोग हैं, ...(**व्यवधान**)... शैक्षणिक संस्थाएं जैसे अस्पताल, स्कूल और कॉलेज हैं, इन सभी को सस्ते मूल्य पर जमीन आबंटित की जाए। दिल्ली वासियों का अपना घर होने का एक सपना था। उसका सपना था कि उसका भी एक छोटा सा घर हो। उस सपने को पूरा करने के लिए ही डी॰डी॰ए॰ का गठन हुआ, मगर 1999 और 2003 के बीच डी॰डी॰ए॰ में एक नेक्सेस बना ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बोलने दें।

प्रो॰ राम देव भंडारी: पोलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में मुकदमे हुए और समाचारपत्रों में सब कुछ छपा। वाइस चेयरमैन खुद गिरफ्तर हुआ, कमिश्नर गिरफ्तर हुआ। ये सब तो गिरफ्तार हुए, लेकिन जो घोटाले करवाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: यह नेक्सेस पोलिटिसियंस और ब्यूरोक्रेसी का था। इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग तो पकड़ में आए, मगर जो पोलिटिसियंस हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, यह अन्याय है, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बोलते जाइए, बोलते जाइए। मुझे देखिए, इनको मत देखिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: अगर ये हमको दागी बताते हैं, तो बीस हजार करोड़ के घोटाले में जिन लोगों का हाथ है, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, इसीलिए मैं आपके माध्यम से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस घोटाले में जमीन की लूट-खसोट हुई है, जनता की सम्पत्ति की लूट-खसोट हुई है, उसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया जाए। इसके साथ ही इसकी समय-सीमा निर्धारित कर दी जाए कि इतने समय में आयोग जांच रिपोर्ट दे देगा और उसके साथ सरकार सख्ती से कार्यवाही करेगी। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI GHULAM NABI AZAD): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to the hon. Members for their keen interest in the whole matter pertaining to development of facilities in Delhi and the role played by Delhi Development Authority. I am also grateful for the valuable suggestions given by hon. Members during the discussion.

In his Resolution, the hon. Member, Shri V. Narayanasamy, has mentioned that the DDA which was the prime and sole agency created to cater to the housing needs of the people of Delhi, specially the poor and the middle class, has not been able to achieve its objectives. He has further stated that it has fallen short of expectations in providing shelter and other facilities like community centres, hospitals, etc. for the poeple of Delhi. He has also referred to the allotment of land made by DDA to specific organisations during the period 1999-2003 ignoring the requirements of other categories. During his speech, Shri Narayanasamy, has also referred to the housing needs, pending registrants in housing schemes, commercial use of specific community centre land and CBI raids.

In the course of their speeches, Shri Narayanasamyji and other hon. Members referred to specific cases of allotment of land at Rous Avenue and other places by the Land & Development Office and also the rates charged for such land as compared to the market rates.

Sir, at the outset, I would like to inform the hon. Member, the mover of the Resolution, and the other Members that since the subject matter under discussion pertains to Delhi Development Authority, most of the speeches on the two previous Fridays were made, and most of the instances were quoted in the House, were not with regard to DDA, but the L&DO. Since the Resolution is on DDA and the speeches were on the L&DO, I would not like to touch the L&DO part, I would like to confine myself to the Resolution which relates to DDA.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Both are under you.

SHRI GHULAM NABI AZAD: That my be.

SHRI S.S. AHLUWALIA: And if specific cases regarding irregularities committed by L&DO were brought to the notice of...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)...

†श्री गुलाम नबी आजाद: आप अगर थोड़ा सब्र रखते, जो कुछ यहां से सीखा था, वह आप वहां जाकर भूल गए। क्या करें?

†شری غلام نبی آزاد : آپ اگر تھوڑا صبر رکھتے، جو کچھ یہاں سے سیکھا تھا، وہ آپ وہاں جا کر بھول گئے۔ کیا کریں؟

श्री सभापति: चलिए, चलिए।

SHRI GHULAM NABI AZAD: At the outset, I would like to place before the hon. House the various activities of DDA and the role played by it so far in providing housing and other amenities for the people of Delhi.

The DDA was set up under the Delhi Development Act, 1957 to formulate a plan for Delhi and effect its development in a planned manner by way of providing shelter, amenities and facilities to the existing population and also to make provisions for the future growth of the city. In furtherance of its objectives, DDA has so far acquired 69871.22 acres of land and developed the acquired land for residential, commercial, industrial, institutional and other purposes like allotment to Government organisations, land for slum colonies, Cooperative societies etc. It has also undertaken development of green spaces/parks and sports facilities.

Shri Narayanasamy as well as Shri Manoj Bhattacharya and Shri Rajiv Shukla mentioned about the need for construction of houses by DDA for the poor. Shri Narayanasamy also referred to a large number of persons registered with DDA for houses and still waiting for allotment. In this connection, I would like to mention that in the housing sector, DDA has, since inception, constructed 2.90 lakh dwelling units, out of which 55,000 belong to High Income Group category, 64,000 to Middle Income Group category and 1.71 lakhs to Low Income Group and Economically Weaker Sections categories. Housing for Low Income Group and Economically Weaker Sections, thus, constitute nearly 60 per cent of the total units

†Transliteration of Urdu script.

constructed by DDA. In addition, the DDA has facilitated construction of over 7.5 lakh dwelling units by way of providing land to individuals, cooperative group housing societies, resettlement colonies, etc. The DDA has so far taken up 41 housing schemes, out of which 36 schemes have been closed. Only five schemes are still alive. Out of these, there is a backlog of 14,741 registrants in three schemes, namely, the New Pattern Registration Scheme-1979, Ambedkar Awas Yojana-1989 and Janta Housing Scheme, 1996. The DDA expects to liquidate these pendency by December, 2005. The other two live schemes pertain to Rehabilitation of Punjab Migrants and Rehabilitation of Kashmir Migrants.

Sir, during the last five years, the DDA has constructed more than 28,332 houses, out of which, 4,865 come under the High Income Group category; 3,899 under the Middle Income Group category and 19,568 under the Low Income Group and economically weaker sections category. Further, more than 23,000 houses are presently under construction at different locations like Dwarka, Rohini and Narela, out of which, 4,695 are meant for the Higher Income Group category, 2,861 for the Middle Income Group category and 15,460 houses for the Low Income Groups and the economically weaker sections cetegory, which constitutes 67 per cent of the total. This would show the efforts made by the DDA to provide houses for different categories of population.

Sir, it would also be evident from the data that special emphasis has been given to the Low Income Group and the economically weaker sections. I may also mention that in the allotment of flats, the DDA reserves 25 per cent of the flats for the SC/ST category, one per cent for physically handicapped persons. one per cent for ex-servicemen and one per cent for war-widows.

Sir, Shri Rajeev Shukla and Shri Balbir Punj had commented about the quality of construction undertaken by the DDA. In this context, I would like to mention that the DDA has been making efforts to improve and upgrade the quality of construction undertaken by it. Besides, regular arrangements for quality check through DDA's Quality Control Unit, third party quality assurance check has also been introduced by utilising the services of reputed organisations like the Central Building Research Institute, the Central Road Research Institute and the IIT, Delhi. The DDA is also making consistent efforts to upgrade specifications of various houses constructed by it.

Shri Balbir Punj also mentioned that there are no takers for the DDA flats. On this, I would also like to mention about the response received by the DDA to the housing schemes launched by it during the last six months. Under the scheme for Two-Bed Room Flats, launched by the DDA in July, 2004, 93,000 applications were received against 2300 houses offered in the scheme. Similarly, in the Festival Housing Scheme, which was launched in November, 2004 against 2500 houses offered by the DDA, 1,64,000 applications were received, which clearly shows overwhelming response for the flats constructed by the DDA. Sir, the DDA has also developed commercial places that include nine district level commercial centres, 50 community centres, 157 local shopping centres and 459 convenient shopping centres to facilitate day-to-day and other commercial requirements of the people. For providing better living and environment. DDA has laid special emphasis on development of green areas. So far, 12,476 acres of land have been developed as green area that includes four regional parks, 111 district parks, 255 neighbourhood parks and 25 city forests. DDA has also developed fourteen integrated sports complexes in different parts of the city.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND) in the Chair]

In so far as allotment of land is concerned, DDA provides land for residential, commercial and institutional purposes covering educational institutions, hospitals, community halls and social, cultural and religious activities, etc. Commercial land is disposed of through auction. In the residential category, land is allotted at pre-determined rates only in the case of plots for Rohini registrants, allotment of alternative plots to persons whose lands are acquired, who are sponsored by the Government of NCT of Delhi and to cooperative group housing societies. Other individual residential plots are disposed of through auction. In the case of hospitals, land was earlier allotted at Institutional Zonal Variant Rates. Since 2001, plot for hospitals, nursing homes are being disposed of through auction. DDA provides land for various institutional purposes like schools, colleges and other educational institutions, social, cultural, and religious institutions etc. on allotment basis as per the provisions of the Nazul Rules and at institutional, zonal variant rates. So far DDA has allotted about 3500 plots to various categories of institutions. In addition, DDA allots land to Government organsiations/local bodies for the purpose of schools, community halls, bus terminals, police stations, mother dairy, electric

sub-stations, water pumping stations, hospitals, Delhi Metro, fire stations etc. Since the year 1999 DDA has allotted land to 921 institutions, out of which 490 allotments, which constitutes nearly 53 per cent, are meant for Government agencies/local bodies, while 431 allotments have been made to various categories of non-Governmental institutions. Out of these, 44 were meant for community halls, 49 for religious institutions, 8 for hospitals, 7 for clubs, 76 for various social, political, cultural organisations and 284 for educational institutions which include nursery schools, primary schools and secondary schools. Allotment of land is made by the DDA to institutions under the provisions of Nazul Rules and other guidelines in force and after taking into consideration the recommendations of various authorities. DDA has been making constant efforts to improve and streamline the procedure and system of disposal of land. It has also been switching over to disposal of land by way of auction in various categories, where the institutions are being run on commercial lines. Apart from hospitals, DDA has also decided to auction the plots meant for clubs and professional and technical colleges/institutions to ensure greater transparency in the method of disposal.

Allotment of institutional plots at Zonal Variant Rates is made on the basis of sponsorship from the State or the Central Government and on the recommendations of the Institutional Land Allotment Committee set up in the DDA. In its meetings held in February, 2003, the Committee had made recommendations for allotment of land in respect of 286 societies. There were complaints in respect of some societies. The DDA then got the matter investigated through its vigilance wing and referred the matter to the Government of NCT of Delhi and the sponsoring authorities. The Government of NCT of Delhi initially withdrew all sponsorships. Later on, after enquiry, it found 166 cases fit for consideration. Sir, 19 cases are presently under investigation by vigilance wing of the DDA.

Sir, the CBI had also undertaken *suo moto* investigation in six cases. Out of 286 cases, initially recommended by the Institutional Land Allotment Committee, land has so far been allotted by the DDA in 54 cases. Out of these cases, three allotments have subsequently been cancelled. Two of these relate to community hall sites given to Sarv Dharam Welfare Society and Sanskrit Society which were unauthorisedly used as banquet halls. These cases were referred to by Shri Narayanasamy in his speech. The third relates to an educational society which failed to make payment on time. The remaining cases are under consideration.

Sir, Shri V. Narayanasamy had referred to the CBI raids on the DDA officials. During the time, a large number of allotments to various institutions were recommended by the Institutional Allotment Committee in February, 2003. There were CBI raids against senior officers of the DDA, followed by arrests and investigations. The set up at the top level has since been changed.

The new regime introduced various systematic improvements to bring in a greater transparency and accountability in the functioning of the DDA. They are: simplification of procedures, increasing computerisation in different spheres of activities, outsourcing of collection to banks, strengthening the public redressal mechanism and counselling services, dissemination of information to public through websites, kiosks, etc., have been put in place. The allotment procedures have also been reviewed for having transparency and objectivity in the entire process. Allotment to clubs, professional colleges and institutions is now done through an auction process. Even the existing procedure for allotment to institutions is under review. This is what I would like to mention to the hon. member. I would also like to say that the remaining cases, which were recommended by the Institutional Allotment committee and cleared by the Government of NCT of Delhi for allotment, have also been put on hold.

It is, thus, a fact that actions were initiated against key officials who were also replaced. A large number of institutional reforms were initiated thereafter to bring in transparency in the entire procedure. The hon. Members have also mentioned the need for reforms in the DDA to improve its functioning so that the people at large are benefited. I would like to assure the hon. Members that the functioning of the DDA, which is a premier institution meant, for development of the Capital City of Delhi, shall be further improved with a view to bringing in still greater transparency, accountability and people-friendly approach. At the outset, I had mentioned that I would not cover the cases relating to the Land & Development Office since the Resolution pertains to the DDA. However, it is for Mr. Ahluwalia, I would like to put the record straight on the issue referred to by the hon. Member, Shri Balbir Punj. This concerns the allotment of land made for the Jawahar Bhavan Trust and the Rajiv Gandhi Foundation. As per records, the position is as follows: 4,736 square yards of land was initially allotted to the Congress Bhavan Trust on 4.9.1975, that is, thirty years back. The allotment was changed in July, 1976 in the name of Jawahar Bhavan Trust. Additional land of 4,583 square yards was allotted in favour of the Jawahar Bhavan Trust on 21.12.1976. The total land of just 1.92 acres—not even

two acres; less than two acres—was allotted for the construction of the office building of the All-India Congress Committee. In July, 1978, when the Janta Party was in power, the allotment was cancelled by the Government in power at that time. (*Interruptions*)

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, यहां से लेकर आपने उन लोगों को मंत्री बनाया है। उस तरफ आप ध्यान दीजिए।...(**व्यवधान**)

†**श्री गुलाम नबी आजाद:** प्लीज, प्लीज। अहलुवालिया जी को परेशानी नहीं है, आपको क्या परेशानी है? ...(**व्यवधान**)...

†شری غلام نبی آزاد : پلیز، پلیز۔ اہلووالیہ جی کو پریشانی نہیں ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟...مداخلت...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, उस समय की सरकार के लोग आपके यहां मंत्री बने बैठे हैं। आपके साथ सत्ता में बैठे हैं। आप 78 की जनता पार्टी की सरकार की जो बात कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Pany, let the hon. Minister complete his reply. (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Again in March, 1988 the cancellation was revoked and the allotment was restored. A lease deed for the entire land was executed in favour of the Jawahar Bhavan. So, the mention that the land was not in the name of the Trust, it is in the name of the Congress Party, was not correct. I would like to make it clear that the lease deed for the entire land was executed in favour of the Jawahar Bhavan Trust on 22.9.1988 by the Land & Development Office. I would like to make it clear that there was no change in land use. I would also like to mention that the area as per land use was meant for social and cultural institutions. In December, 1995, permission was given to the Trust for use of a maximum of 40 per cent of the built up space by the Rajiv Gandhi Foundation. So, it is not an unauthorised occupation by the Trust. It is under rules only that the 40 per cent built up area was given to the Rajiv Gandhi Foundation. I would also like to make it clear since the dispensation of sub-letting is permitted to the extent of 40 per cent to all the institutions, there was no deviation from the prevailing rules. This is for all institutions. That means all the allotments and the giving of 40 per cent to the Rajiv Gandhi Foundation was under rules. No deviation has taken place. Sir, this was a specific mention. I have not touched other specific mentions which my friend ...(*Interruptions*)

†Transliteration of Urdu script.

SHRI GHULAM NABI AZAD: No, I am mentioning this because if I had not mentioned this my hon. friends would have said that I am deliberately skipping the allotment just for this case. So, let it be clear that I have not skipped that. I have made it clear. (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am not disputing anything what you said because I know the whole history. My point is very simple. From this statement it is coming out, and one can draw a conclusion, that this is not a new thing. The previous Government allotted some land. Some other regime came and they have cancelled it; instituted an inquiry or penalised the other people. This process is going on continuously. How long will it go? It should be stopped.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am not again making any mention of Rouse Avenue—though I can make it—because now I have already tabled the Report also. But the difference here and there is that everything is in order. This particular land was for institutions. This particular land was not for residence. But, the other issues, which have come, I would again request my friend, he can bring them on some other occasion because the whole land belongs to L&DO. The irregularities are that the land meant for something else has been given to somebody else. किसकी टोपी किसी के सिर पर डाली है। There is no fulfilment of requirements. If the requirements, if the conditions are fulfilled, nobody will have any objection either on this side or that side. So, there also we have dealt with only those cases where the basic requirements which a society, an institution, a school, a hospital, is supposed to fulfil. Those requirements have not been fulfilled. That is why there is an objection. As I have said earlier, it is a separate subject. Now, I have laid the report on the Table of the House. In the next Session you can ask for the debate. I will be ready to debate that. But, I don't want to mix the Resolution which is meant for DDA, and have discussion on L&DO.

Further, as indicated earlier, investigations at various levels are also being carried out in respect of various cases where allegations/complaints have been received by DDA. Considering the matter in total perspective, I am of the opinion that further inquiry into the matter by a Commission is not necesary.

Keeping this in view, I would request the hon. Member to withdraw the Resolution. At the same time, as I have said...(*Interruptions*) As I have already said, the CBI is already inquiring into a number of cases. It is at various stages of action. So, let the CBI complete its investigation and

even after the CBI investigation, if there are some doubts, I will definitely see what best can be done to bring the truth before the House. Thank you.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am not fully satisfied with the reply given by the hon. Minister in this House. (*Interruptions*) I am not satisfied, I have told that. (*Interruptions*) Sir, I am very grateful to the hon. Members, Prof. Ram Deo Bhandary, Shri Rajeev Shukla, Shri Balbir K. Punj, Prof. P.J. Kurian, Shri Manoj Bhattacharya and Shri Sharad Ananadrao Joshi, who have participated in the discussion. The hon. Minister has admitted that vigilance inquiry is going on. The hon. Minister has admitted that the CBI inquiry is going on. The hon. Minister has also admitted that there are irregular allotments. Allotments were made to the same organisation three or four times. (*Interruptions*) I am going to give the entire list to the hon. Minister. Right from 1995 to 2003, I have the entire list with me. If the hon. Minister wants, I will place it on the Table of the House. (*Interruptions*) The hon. Minister has also admitted that additional lands were given to the same organisations. Additional lands were given and allotments were made to large number of societies, which has got RSS links. Former Union Minister and officials in the Prime Minister's Office were given DDA land in the Rohini area. A former Union Minister also got allotment of land for a school. The NDA's Labour Minister *got it.*got it. The other gentleman, *got it. *got it. Sir, it is a big scandal, 'scandal of the century' you can say, because right from 1999-2003, I can show it to the hon. Minister that all are RSS-affiliated organisations. And, Sangh Parivar..(*Interruptions*) ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Narayanasamy, please don't mention the names of those who are not present here, and those who can't afford..(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I can prove it..(*Interruptions*) I am speaking in ...*(Interruptions)*... Sir I can prove it ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Narayanasamy, you have given a detailed..(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): If you can authenticate those papers, then lay them on the Table of the House, Sir..(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am prepared to do it..(*Interruptions*).. because it is a public document. It has been taken from the

*Expunged as ordered by the Chair.

Internet..(*Interruptions*).. These documents have been taken from the Internet. Delhi Development Authority has published it..(*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Narayanasamy, during the course of your discussion, you have made a detailed submission..(*Interruptions*)..

SHRI V. NARAYANA SAMY: Sir, ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Narayanasamy, will you please yield for a minute. Sir, I have a procedural question. Sir, since the Member concerned, with all sense of responsibility, is quoting all these things, and he is prepared to authenticate then, Sir, please direct him, because all this information is already a property of this House. Therefore, let him authenticate..(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Basu, he can't place at the Table of the House at this stage. He has to seek permission of the hon. Chairman.

SHRI NILOTPAL BASU: But, Sir, he is prepared to authenticate..(*Interruptions*)..

SHRI V. NARAYANASAMY: I am prepared to authenticate it...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: Just a minute, this is a procedural question. Sir, you are well within your rights, as the Presiding Officer, to allow him to authenticate and place it on the Table of the House. At least, this should become the property of the nation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Basu, full-fledged discussion has already taken place.

SHRI NILOTPAL BASU: No, but..(*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): The hon. Minister has given a detailed reply. Now it is for Mr. Narayanasamy, the Mover of the Resolution, whether he wants to withdraw it or not..(*Interruptions*).

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, please allow me. This is a procedural question that in the format of the Private Members' Resolution, it is not the concerned Minister who replies to the debate. He replies to the question raised by the Members. And, actually, the right to reply is of the Mover of the Resolution. So, while concluding that debate, when the

Mover of the Resolution is making very important points, and giving some information which is very important for the country, I think, there is a right for me, as an individual Member of this House to say that he should authenticate and lay the papers on the Table of the House. Sir, please ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): He had the full opportunity...*(Interruptions)*... At that time also, he had all the relevant papers with him...*(Interruptions)*...If he wanted to place these documents...*(Interruptions)*...he could have placed them...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, it will be arrogant on my part to say that in the Rules Book, it is provided that while he is exercising his right to reply, if he reveals certain information, there is every right for each and individual Member of this House to ask for authentication and laying of those papers on the Table of the House...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Ahluwalia, please...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, please give your ruling on this.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, the discussion has already been concluded.

SHRI V. NARAYANASAMY: No, it is not concluded...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I again raise the question of procedure...*(Interruptions)*...Reply is part of the discussion, Sir...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Basu, you have made your submission, let Mr. Ahluwalia speak.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, the discussion has already been concluded The Minister has given the reply, and while replying...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: No, no; the Minister has intervened, Sir...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Narayanasamy, please listen to me...*(Interruptions)*...

3.00 P.M.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I am on a point of order. If the discussion is concluded, under what rule he is speaking...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Basu, you have made your point...*(Interruptions)*...Let Mr. Ahluwalia speak...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, if the discussion is concluded, in what capacity he is speaking...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I am also speaking on a point of order...*(Interruptions)*...Let me finish...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, the discussion is continuing, and the discussion will only be over when the right to reply by the Mover of the Resolution will be concluded...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): I have identified Mr. Ahluwalia...*(Interruptions)*... Please sit down...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, while intervening, the Minister...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I fail to understand how such a senior leader like Mr. Ahluwalia does not know this preliminary thing about the procedure...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Let me finish. ...*(Interruptions)*... What is this? ...*(Interruptions)*,.. why are you jumping to conclusions?...*(Interruptions)*... Please hear me.

SHRI NILOTPAL BASU: We are hearing.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, what I am saying, Sir, is that the Minister has already said on the floor of the House that he has yesterday laid a report which has looked into the whole matter. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: No; no; that is a different thing. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: So, he said that the report is already laid on the Table of the House, and we can take it up for discussion. And, if at all, he is still curious to lay any paper which he can authenticate, he is welcome

to do that. But don't create a bad precedent in the House because papers surround everywhere. It is not only you who gets papers; I also get papers. So, you create a precedent and then face the consequences. ...*(Interruptions)*... My point is simple. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I am on a point of order. ...*(Interruptions)*... He is threatening that 'if you authenticate that paper and lay it here, well face the consequences'. ...*(Interruptions)*... I would like to see it as a threat. I want your protection. Is it a threat? ...*(Interruptions)*... What he means is that 'if you make a precedent, where you authenticate your papers and lay it on the Table of the House, well, you mind it, I have got a number of papers. I can also give it.' ...*(Interruptions)*... This is what exactly is happening in this House. ...*(Interruptions)*... We do not want all these threats and counter-threats. I want to protect the names, which he has uttered. I am not protecting them; I am protecting the names, which he has uttered. Some of them are very revered leaders; some of them are very respected leaders in Delhi. Mr. Tytler must be knowing it. Some very respected leaders of Delhi have been named by him. Sir, I want to protect their names. If he has the courage, let him give those names, and authenticate it. ...*(Interruptions)*... They are revered, respected leaders. They are not *agees;* they are not *dagees.* ...*(Interruptions)*... They are not *dagees.* ...*(Interruptions)*... Some people talk about *dagee* Ministers. They are not *dagees.* ...*(Interruptions)*... Such respected leaders of Delhi have been named. ...*(Interruptions)*... I want to protect their names. He must authenticate and submit it; otherwise, he should apologise to the House. ...*(Interruptions)*... I want to protect the names of the respected leaders of Delhi whose names he has uttered. And, I say, Sir, to protect the names, either he should authenticate and submit it, or, he should withdraw it. ...*(Interruptions)*... Or, I may have to move a Motion of Privilege against him. ...*(Interruptions)*... They are not *dagees;* they are very respected people who have been named. दिल्ली के सब बड़े-बड़े आदमी हैं। They are not *dagees;* they are not Yadavs; Sir, they are very big people. ...*(Interruptions)*... They are not Yadavs and Paswans. They are very big people. They are not *dagees.* ...*(Interruptions)*...

PROF. P.J. KURIAN (Kerala): Sir, I am only submitting that this is a Private Member's Bill that is being discussed. You see, in an ordinary Bill, what right a Minister has, the same right a Private Member has, equal right. If the Minister in a ...*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: That point has been made.

PROF. P.J. KURIAN: Let me say. If a Minister in a reply can place a paper on the Table of the House, a Member who is replying also can do so. Secondly, in this case, the Minister was only intervening. The right of reply is with the Private Member, the Mover of the Resolution. Therefore, he has every right to give any new information because we were all putting questions and he is to reply to those questions. He has every right to give any new information, including whatever he got from the Website of the DDA. ...*(Interruptions)*... Therefore, Sir, it has to be permitted. Otherwise, it is a wrong precedent, if it is not permitted. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Vice-Chairman, Sir, now you have heard everybody. We would like to hear your ruling on this. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: ...whether it is authenticated or not. Otherwise, I will move a Motion of Privilege against him. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: I am prepared to lay it on the Table of the House even now. I am prepared to authenticate the document. This has been taken from the Website. ...*(Interruptions)*... Sir, I am prepared to authenticate it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Narayanasamy, will you, please, sit down? There is a procedure for laying of papers by private Members. This is given in the 'Directions by the Speaker, Lok Sabha'- 5th Edition, 118, sub-clause 1...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, we do not quote from the Lok Sabha...*(Interruptions)*...We quote only from Rajya Sabha's conventions...*(Interruptions)*...we quote only from Rajya Sabha's conventions...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: It can be quoted from anywhere ...*(Interruptions)*...

PROF. P.J. KURIAN: We don't quote from the Lok Sabha...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, we quote here the Parliament...*(Interruptions)*...We quote from the House of Lords, from the House of Commons and you are saying that we cannot quote from the Lok Sabha!...*(Interruptions)*...

PROF. P.J. KURIAN: Sir, directions from the Lok Sabha cannot be quoted here and likewise, Rajya Sabha directions cannot be quoted in that House...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the proceedings and discussions of the Lok Sabha cannot be quoted here...*(Interruptions)*...they cannot be quoted here...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is not correct...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Ahluwalia, if every Member says that 'an hon: Member from Lok Sabha said this, I am prepared to authenticate'...*(Interruptions)*...

श्री दीपांकर मुखर्जी: आपने कैसे नाम ले लिया उनका? इतने महान नेताओं का नाम लिया, दिल्ली वाले क्या सोचेंगे? अब तो खबर पहुंच गई होगी। यह तो बहुत बुरी बात है। हाथ जोड़कर माफी मांगो। ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, यह तो बुरा होगा कि प्रोसीडिंग्ज़ में आ गया और ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है।

SHRI V. NARAYANASAMY: If you want me to authenticate...*(Interruptions)*...I am saying this on the floor of this House...*(Interruptions)*...Why are you asking me this?...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Hon. Members, I have heard both the sides. I will examine the papers and then take a decision on laying of the documents.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, till such time, it may be deferred...*(Interruptions)*...till such time the papers are being examined, the discussion may be deferred. Otherwise, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, if I want to lay the papers and authenticate them and if somebody tells me that if you do it, I would also do it, सर, यह तो ठीक नहीं है। The threat which has been used here by saying that we should not set wrong precedents...*(Interruptions)*...if he says it, as for precedents...*(Interruptions)*...if he has said that if you bring some papers, I would also bring some papers, यह तो ठीक नहीं है।..*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: I didn't say that...*(Interruptions)*...I didn't say that...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Why do you say that threat is being given...*(Interruptions)*...He is denying that and still you say that threat has been given...*(Interruptions)*...You keep saying that he has threatened.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, papers are found everywhere ...*(Interruptions)*... I can bring tons of papers here...*(Interruptions)*...That is not the point...*(Interruptions)*...That will be a bad precedent...*(Interruptions)*...सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री रंगनारायण पाणि: यह कोई थ्रेटनिंग नहीं है।...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, you have given a ruling. I respect your ruling. Since you wished to go through the documents, till such time it is being done, the discussion may be deferred...*(Interruptions)*...But if you agree to my...*(Interruptions)*...If you are willing to take up another Resolution, till such time, the discussion may be deferred...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (SHRI JAGDISH TYTLER): Sir...*(Interruptions)*...he has downloaded the papers from the official website of DDA...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I suggest that till such time it may be deferred and in the meanwhile, the next Resolution may be taken up for discussion.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (Uttaranchal): Sir, the next Resolution may be taken up for discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): At this point of time, the discussion on this Resolution is deferred...*(Interruptions)*...We can take up the next.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, why do you want it to be deferred? Why do you want to see the papers? If he wants to lay the papers, let him do so. क्या दिक्कत है? If they want to create a bad precedent in the House, let them do it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Mr. Narayanasamy, please submit your papers, I shall examine them...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Okay, Sir...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): You may, please, continue with your speech if you so wish.

SHRI V. NARAYANASAMY: But, Sir, you have already said that you are deferring it. After you have taken a decision on that, it may be taken up...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM NATH KOVIND): Even after you complete your submission...*(Interruptions)*...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, the next Resolution may be taken up for discussion...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I told the hon. Minister very clearly that no *inter se* seniority was considered. People, who had applied 20 years back or 30 years back, were ignored. People, who had applied only two years back, were given the allotment. Apart from that, the Chairman, D.D.A.—everybody knows it—took a decision. While taking the decision, the Board Members were not taken into confidence. Even the Board Members wanted C.B.I. enquiry. They demanded C.B.I. enquiry. Apart from that, even the norms for allotting the land were openly violated. The plot sizes were carved out basing on various considerations. Thirdly, as I mentioned it earlier, the allotments were made to societies to construct a college. Before the college gets the recognition, recognition to start a college, those societies were given the land by the allotment authority, and thereafter they applied for the permission to construct a college. It is all there. This is a clear violation. The land has been given for hospital, but they have not constructed hospital. The land has been given for cultural organisation, but they have not done that work. Two hundred and ninety one allotments were made in February 2003. When the Board met on February 13 and February 17, they cleared only 20 or 30 allotments. Two hundred and ninety one allotments were given, and in these allotments, as the hon. Minister said, C.B.I. enquiry has been ordered, and C.B.I. enquiry which was ordered in September, 2003 was shelved. The D.D.A. officials went to the C.B.I. office and they wanted to get those documents from them. Now, when the new government come, C.B.I. started the enquiry.

This is a clear violation of the rules and regulations. Apart from that, it is a clear violation of the autority vested with D.D.A. Sir, everything was being done. If anybody demands, I would like to say that it was totally under monarchy of one person, the Lieutenant Governor of Delhi, who has made the allotments left, right and centre. Therefore, it is a clear case of violation of rules, norms, guidelines, and one organisation has been given five times the allotment or four times the allotment. Under what consideration, we do not know. The hon. Minister has agreed for the vigilance enquiry. The hon. Minister has agreed that vigilance enquiry is going on; C.B.I. enquiry is going on. He is also agreed that several allotments have been cancelled, and he has said that allotments have been withdrawn. The hon. Minister has said all these things. Therefore, I want the hon. Minister to reconsider his decision. Let him say that he will order enquiry, there is no difficulty. Let the truth come out. Let the people of Delhi, especially people who were waiting for allotment for years together, around 50,000 people have been waiting for allotment for construction of houses---the Government servants, the other public ---- and they are not able to get it. It has been given to certain people by the previous D.D.A. Chairman. Therefore, I want a full-fledged enquiry and I request the hon. Minister for it. Before concluding, if the hon. Minister gives a satisfactory reply, I am prepared to withdraw. I want the hon. Minister to agree for enquiry, then I am prepared to withdraw,

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I have said in the beginning only that already, Vigilance inquiry is going on, and CBI inquiry is going on. So, at a time, how many inquiries one can have? Let these inquiries come to some conclusion. After these two inquiries are through, and even after that, if there are some doubts, I will definitely do something to satisfy the hon. Member and also the hon. House. It may be the.....(*Interruptions*).....the Commission has yet not.....but, even after that, if it is required, or there is need, we will definitely do something.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, for the benefit of the hon. Minister, I am giving him certain papers.

SHRI GHULAM NABI AZAD: You can give this to me. Now, I would request Mr. Narayanasamy to withdraw the Resolution. I hope, he is now satisfied.

SHRI V. NARAYANASAMY: As the hon. Minister has given an assurance, I am satisfied. I withdraw the Resolution.

The Resolution was, by leave, withdrawn.